

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मई 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (1986), प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अध्यक्ष, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को केवल अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

3. श्रीमती रेणु जी पिल्ले, भा.प्र.से. (1991), अपर मुख्य सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर को अपर मुख्य सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग प्रभार से मुक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

श्रीमती रेणु जी पिल्ले, भा.प्र.से. द्वारा अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997), सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

4. श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-निवेश, आयुक्त, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC), (मुख्यालय दिल्ली) तथा प्रमुख सचिव, वन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994) द्वारा आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली केवल आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

5. श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

6. श्री भरत लाल बंजारे, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

7. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, सहकारिता विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा आयुक्त, निःशक्तजन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, कौशल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003), सचिव, लोक निर्माण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, रायपुर केवल सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

8. श्री अम्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, खनिज साधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

9. श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

10. डॉ. संजय कुमार अलंग, भा.प्र.से. (2004), कलेक्टर, जिला-बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

11. श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2004), अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर एवं सचिव, लोक आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है।

12. श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), कलेक्टर जिला-दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है।

13. श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005), द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री हेमंत पहारे (से.नि. भा.प्र.से. संविदा नियुक्ति), केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

14. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006), कलेक्टर, जिला दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

15. श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

16. श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006) द्वारा विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री हेमंत पहारे (से.नि. भा.प्र.से. संविदा नियुक्ति), केवल सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे।

17. सुश्री शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड), रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ करता है।

18. श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), पंजीयक, सहकारी संस्थायें तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, प्रशासन अकादमी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

19. श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है।

20. श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करता है।

21. श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

22. श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा संयुक्त सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पद पर पदस्थ करता है।

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

23. श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियंत्रक, नाप-तौल के पद पर पदस्थ करता है.

श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियंत्रक, नाप-तौल के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

24. श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ करता है.

25. श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जशपुर के पद पर पदस्थ करता है.

26. श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के पद पर पदस्थ करता है.

27. श्री नीलकंठ टीकाम, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के पद पर पदस्थ करता है.

28. डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से के आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

29. श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

30. श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है.

31. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है.

32. श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

33. श्री जय प्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है.

34. श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-महासमुंद के पद पर पदस्थ करता है.

35. श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर पदस्थ करता है.

36. श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।
37. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मुंगेली के पद पर पदस्थ करता है।
38. श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कबीरधाम के पद पर पदस्थ करता है।
39. श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-जशपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
- श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
40. श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है।
41. श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है।
42. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है।
43. श्री जन्मेजय महोबे, भा.प्र.से. (2011), आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बालोद के पद पर पदस्थ करता है।
44. श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ करता है।
45. श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है।
46. श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है।
47. श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है।
48. श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य कौशल विकास अभिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है।
49. श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ करता है।
50. श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), अपर कलेक्टर, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. स्टेट वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

51. श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है।

52. श्री एस. जयवर्धन, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है।

53. श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन उप सचिव, छ.ग. राज्य योजना आयोग एवं उप सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

54. श्री राहुल देव, भा.प्र.से. (2016), आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है।

55. श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), सहायक कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जून 2020

क्रमांक एफ 10-01/2019/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री एलेक्स व्ही.एफ. पॉल मेनन व्ही. (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए “मुख्य सुलहकार” नियुक्त करता है।

No. F 10-01/2019/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the Subject, State Government hereby appoints Shri Alex V. F. Paul Menon V. (IAS) Labour Commissioner to be “Chief Conciliator” for the State of Chhattisgarh.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जून 2020

क्रमांक एफ 10-01/2019/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (सन् 1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री एलेक्स व्ही.एफ. पॉल मेनन व्ही. (भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए “श्रम आयुक्त” नियुक्त करता है।

No. F 10-01/2019/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the State Government hereby appoints Shri Alex V. F. Paul Menon V. (IAS) as the “Labour Commissioner” for the State of Chhattisgarh.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जून 2020

क्रमांक एफ 10-02/2017/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक-XIV 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा यह निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा-34 के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य शक्ति श्री एलेक्स व्ही.एफ. पॉल मेनन व्ही. (भा.प्र.से.) श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग में लायी जावेगी।

No. F 10-02/2019/16.—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Dispute Act, 1947 (No. XIV of 1947) and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby directs that powers under Section 34 of the said Act shall be exercised by Shri Alex V.F. Paul Menon V. (IAS) Labour Commissioner, Nava Raipur, Atal Nagar for the State of whole Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 जून 2020

क्रमांक आर. 2192/5048/2017/11/(6).—राज्य शासन एतद्वारा राज्य में स्थित उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट का नियमानुसार अपवहन (डिस्पोजल) किये जाने हेतु ग्राम-केसदा, रा.नि.मं. तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की 50 एकड़ भूमि (खसरा क्रमांक 1004 से 1022 तक एवं खसरा क्रमांक 1027, 1028 कुल रकबा 20.410 हेक्टेयर अर्थात् 50.43 एकड़) को परिसंकटमय अपशिष्ट के अपवहन के लिए कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी (CTSDF) की स्थापना हेतु अधिसूचित करता है।

इस अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन द्वारा श्री मयंक श्रीवास्तव, (भापुसे-2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं/यातायात, पुलिस मुख्यालय रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निदेशक, ट्रेनिंग आपरेशन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. श्री मयंक श्रीवास्तव, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 2016 के नियम-12 के तहत निदेशक, ट्रेनिंग आपरेशन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के समकक्ष घोषित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जून 2020

क्रमांक/4182/एफ-02/02/WBCIS/2020/14-2.—उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिसूचना क्र. 4049/एफ-02/02/WBCIS/2020/14-2 दिनांक 22-06-2020 जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्र. 3 (ख) अन्तर्गामी कृषक में उल्लेखित “इस हेतु कृषक को फसल बुआई प्रमाण पत्र या बुआई के आशय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा” के स्थान पर “इस हेतु कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा” पढ़ा जावे।

शेष प्रवर्ती शर्तें अधिसूचना क्र. 4049 दिनांक 22-06-2020 के अनुरूप होगी।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जून 2020

क्रमांक/4184/एफ-02/01/PMFBY/2020/14-2.—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिसूचना क्र. 2976/एफ-02/01/PMFBY/2020/14-2 दिनांक 16-06-2020 जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

अधिसूचना के बिन्दु क्र. 3 (ख) अन्तर्गामी कृषक में उल्लेखित “इस हेतु कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई की पुष्टि का प्रमाण-पत्र जो क्षेत्रीय ग्रा.कृ.वि. अधिकारी द्वारा सत्यापित हो सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा” के स्थान पर “इस हेतु कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा” पढ़ा जावे।

शेष प्रवर्ती शर्तें अधिसूचना क्र. 2976 दिनांक 16-06-2020 के अनुरूप होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव।

जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 01-01/2019/चौबीस.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-08-2019 द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमन्यता नियम 2019 के नियम 5 अनुसार राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अधिमन्यता समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन एतद्वारा उक्त राज्य स्तरीय समिति में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

“राज्य स्तरीय अधिमन्यता समिति के सरल क्रमांक 4. श्री आलोक मिश्रा, संपादक, नई दुनिया, रायपुर के स्थान पर श्री मनोज कुमार झा, राज्य संपादक, नई दुनिया, रायपुर को मनोनित करता है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव।

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2020

क्रमांक-एफ 7-20/2019/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बिरकोना निवेश क्षेत्र, जिला कवर्धा का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैं :—

अनुसूची

बिरकोना निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में** : ग्राम घुघरीकला, पालीगुड़ा एवं बिरकोना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बिरकोना, खैरझिटी, दुबहा एवं जिंदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम जिंदा, कुटकीपारा, भेदली एवं लिमो ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम लीमो, जुनवानी, मगरदा एवं घुघरीकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 जुलाई 2020

क्रमांक 5666/1556/21-ब/छ.ग./2020.—राज्य शासन, एतद्वारा, अवमानना प्रकरणों में शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की ओर से पक्ष समर्थन करने के लिये नियुक्त विधि अधिकारी/अधिवक्ता को प्रत्येक प्रभावी सुनवाई तिथि हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश देता है कि —

- (1) अवमानना प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण हेतु (चाहे सुनवाई तिथि कितनी भी हो) समेकित फीस रु. 20,000/- नियत किया जाता है. साथ ही एक ही मूल प्रकरण से उद्भूत अन्य समान अवमानना प्रकरण के लिये, जिसमें आवेदक एक ही हो, परन्तु अनावेदक (अवमाननाकर्ता) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी पृथक-पृथक हो, वहां पर रु. 5,000/- प्रत्येक अतिरिक्त प्रकरण/प्रत्येक अवमाननाकर्ता अधिकारी/कर्मचारी की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाये.
- (2) जिस अवमानना प्रकरण में एक से अधिक अनावेदक (अवमाननाकर्ता) हो वहां पर फीस का भुगतान, समस्त अनावेदक (अवमाननाकर्ता) की ओर से प्रथम अनावेदक (अवमाननाकर्ता) की ओर से ही किया जावे.

उपयुक्त मानदंड के अनुसार संबंधित अधिवक्ता के फीस का व्यय उसी मांग संख्या एवं शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा, जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (प्रथम अनावेदक/अवमाननाकर्ता) के वेतन भत्ते आदि आहरित किये जा रहे हैं.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 576/ब-3/2020 दिनांक 16-06-2020 के द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. चन्द्रवंशी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9133/भू-अर्जन/2020.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जटांगपुर	4.652 हेक्टेयर	जटांगपुर एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-6-2020 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन पंडरीपानी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जटांगपुर एनीकट योजना के नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 317.53 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 25 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उद्बहन सिंचाई द्वारा (स्वयं के खर्चे पर) उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 15 जून 2020

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9206/भू-अर्जन/2020.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	सुक्लाखार	4.955 हेक्टेयर	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 8-7-2020 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सुक्लाखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	54 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	54 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

क्रमांक/9130/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कसरेंगा प.ह.नं. 08	1.766	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 12 जून 2020

क्रमांक/9154/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	ढपढप प.ह.नं. 08	2.746	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक/2319/वा./भू.अ./प्र.क्र./5/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-ऐटेगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82/2	0.06
26/2	0.18
75	0.09
76	0.07
74/1	0.02
74/2	0.07
73/1	0.08
72	0.03
71	0.09
69	0.02
68	0.03
66	0.01
35/2	0.04
35/1	0.10
योग	14
	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 22 जून 2020

क्रमांक/2320/वा./भू.अ./प्र.क्र./6/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-आतुरबेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
RF/764	0.27
RF/764	0.10
RF/764	0.18
RF/764	0.13
RF/764	0.24
RF/764	0.10
RF/764	0.10
RF/764	0.07
RF/764	0.58
RF/764	0.79
योग	10
	2.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आतुरबेड़ा जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, अंतागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2020

क्रमांक 85/सी.एस.ई.आर.सी./2020.—विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 42 की उपधारा (5), (6) एवं (7) सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (आर) एवं (एस) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यथा संशोधित विद्युत नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2011, 30 मई 2012 को अधिसूचित किया गया था।

आयोग अनुभव करता है कि देय अपील राशि के एक तिहाई राशि को अपील के पूर्व जमा करने जैसे बाध्यकारी शर्त, जैसा कि उपरोक्त उपभोक्ता परिवेदना निवारण, विनियमों के खण्ड क्रमांक 55 में प्रावधित है, उपभोक्ताओं को न्याय के लिए लोकपाल के समक्ष जाने से हतोत्साहित करती है। यह व्यापक जनहित में तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की उद्देश्यिका में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप होगा कि उक्त खण्ड क्रमांक 55 को उपभोक्ता परिवेदना निवारण, विनियमों से विलोपित किया जावे। विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा आयोग को आदेशित किया गया है कि वह उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और पर्याप्त कारणों तथा तर्कसंगत होने के आधार पर आयोग का यह दृष्टिकोण है कि उपरोक्त प्रावधान को विलोपित करने हेतु विनियामक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आयोग एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है:

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020

अध्याय-1

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ

1. इन विनियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2011 कहा जायेगा।
2. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, उनसे संबंधित अनुज्ञप्त क्षेत्र में लागू होंगे।
3. ये विनियम इनके मूल पाठ के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

परिभाषा :

4. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

“मूल विनियमों” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2011.

अध्याय-2

संशोधन

5. मूल विनियमों का खण्ड 55 विलोपित किया जाता है।

No. 85/CSERC/2020.—In exercise of the powers vested in the Commission under the provisions of sub-section (5), (6) and (7) of Section 42 read with clauses (r) and (s) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) (the Act), and in pursuance of the provisions of Electricity Rules, 2005, as amended, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission had notified the regulations namely Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011 on 04th March, 2011.

The Commission feels that such a condition acts like deposits an amount equal to one third of the amount due as appeal amount before filing of appeal, as provided in Clause No. 55 of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011, is disincentive for the consumers from approaching the Ombudsman for justice. This is in larger public interest and also in sync with the objective outlined in the preamble to the Electricity Act, 2003. As per Electricity Act, 2003 the Commission is mandated to protect the interests of the consumers and for the sufficient reasons and justifications, the Commission is of the view that for omission of the said provision, there is no need to go through the regulatory process. Hence, the Commission hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011, namely :—

**Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers)
(First Amendment) Regulations, 2020**

CHAPTER-1
SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

1. These regulations shall be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) (First Amendment) Regulations, 2020.
2. These regulations shall be applicable to all distribution licensees in Chhattisgarh in their respective licensed areas.
3. There shall come into force from the date of their publication in Chhattisgarh Rajpatra.

Definition

4. In these regulations, unless the context otherwise requires :

“Principal Regulations” means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Redressal of grievances of consumers) Regulations, 2011.

CHAPTER-2
AMENDMENT

5. Clause No. 55 of the principal Regulation is omitted.

आयोग के आदेशानुसार,

एस. पी. शुक्ला,
सचिव.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 4 जून 2020

क्रमांक/204/01/2020-21/स्था.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/एक (1) नवा रायपुर, दिनांक 30-05-2020 के तारतम्य में श्री टामन सिंह सोनवानी द्वारा दिनांक 01-06-2020 को पूर्वाह्न में सदस्य के पद पर एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर दिनांक 02-06-2020 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

हस्ता./-
सचिव.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2018

फा.क्र-18/03/निर्वाचन याचिका/2018/1949.— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 82/छ.ग.-लो.स./ (15/2014)/2018 दिनांक 12 जून, 2018 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106(क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन अर्जी संख्या-15/2014 में दिए गए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के तारीख 20 अप्रैल, 2018 के आदेश को राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

(सुब्रत साहू)
 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 12 जून, 2018—22 ज्येष्ठ, 1940 (शक)

सं. 82/छ.ग.-लो.स./ (15/2014)/2018.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 (क) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्वाचन अर्जी सं. 15/2014 में दिये गये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के तारीख 20 अप्रैल, 2018 के आदेश को प्रकाशित करता है।

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

EP. No. 15 of 2014

PETITIONER : Shambhu Prasad Sharma S/o Late Bansh Gopal Sharma Aged About 70 Years R/o Village And Post-Seoni, Tah. Marwahi, Civil & Revenue Distt. Bilaspur C.G. Chhattisgarh.

VERSUS

RESPONDENTS :

1. Dr. Banshilal Mahto S/o Late Dhaniram Mahto Aged about 73 Years R/o House No. 31, Ward No. 7, Champa Road, Main Road, Korba, Civil & Revenue Distt. Korba Chhattisgarh.
2. Charan Das Mahant S/o Bisahu Das Mahant Aged About 59 Years R/o House No. 623, Mahant Para, Post-Saragaon, Tah. Champa, Distt. Janjgir-Champa Chhattisgarh.
3. Heera Singh Markam S/o Late Dev Sai Markam Aged about 79 Years R/o Village & Post-Tiwrata, Tah. Pali, Civil & Revenue Distt. Korba Chhattisgarh.

4. Jeevan Lal Rautel S/o Bisauha Ram Rautel Aged about 48 Years R/o House No. 224, Kolanpara, Village-Danauli, Post-Korja, Tah. Pendra Road, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
5. Amar Nath Pandey S/o Late Brajraj Pandey Aged About 48 Years R/o H.I.G. 128, M.P. Nagar, Korba Distt. Korba Chhattisgarh.
6. Dhan Singh Dhurve S/o Sri Rangae Dhurve Aged About 43 Years R/o Navgae, Post-Raghunath Nagar, Tah. Wadraf Nagar, Surguja Division, Distt. Balrampur C.G., Pin-497225, Chhattisgarh.
7. Pratap Bhanu S/o Gulab Singh Aged About 45 Years R/o Village & Post-Semardarri, Tah. & Post-Marwahi, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
8. Charan Bhaiyya S/o Ramcharan Aged about 45 Years R/o Girari, Post-Nawagaon, Tah. Pendra Road, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
9. Jata Shankar Pandey S/o Jagdamba Aged About 38 Years R/o Salwa, Post-Ghutra, P.S. Manendragarh, Distt. Korba C.G., District : Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.
10. S. R. Anchal S/o Late Mungeliha Das Aged about 44 Years R/o Dr. Ambedkar Chowk, House No. 632, Ward No. 39, Ayodhyapuri, Post-Ntpc Jamnipali, P.S. Darri, Distt.-Korba Chhattisgarh.
11. Chandra Bhuwan Pratap Singh Kanwar S/o Mool Chand Kanwar Aged about 36 Years R/o Jambahar, Post. Balco Nagar, Civil & Revenue Distt. Korba, Chhattisgarh.
12. Laxman Lal Kaiwarty S/o Birbal Aged About 44 Years R/o Purani Basti, Darri Post.-Jamnipali, Tah. Katghora, Distt. Korba, Chhattisgarh.
13. Phuleshwar Prasad Surjaeeha S/o Shambhunath Surjaeeha Aged about 71 Years R/o Dhinouchi, Post-Siwni, Tah. Marwahi, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
14. Rajesh Kumar Pandey S/o Bharat Kumar Pandey Aged About 42 Years R/o Old Kashinagar Khapra Bhattha, Budhwari Bazar, Korba, House No. 1106, Ward No. 16, Korba, Distt. Korba, Chhattisgarh.
15. Dr. Urmila Singh Marko D/o Rai Singh Marko Aged About 49 Years R/o Behind Seel Colony, Bandhwapara, Sarkanda, Bilaspur, Distt. Bilaspur Chhattisgarh.
16. Harbhajan Singh Shyam S/o Sumer Singh Aged About 33 Years R/o House No. L/101 Chief House Bartunga, Post.-Chirmiri, Tah. Khadgawan, Pin-497449, District : Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.
17. Rajendra Singh Kanwar S/o Late Jai Singh Kanwar Aged About 32 Years R/o House No. 563/1/3 Padhimar Balco Nagar, Distt. Korba Chhattisgarh.
18. Mohan Lal Bargahi S/o Ramadhin Bargahi Aged About 60 Years R/o Ward No. 09, South Jhagrakhand, Tah. Manendragarh, District : Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.
19. Fatte Singh Shyam S/o Jarman Singh Aged About 55 Years R/o Dhinouchi, Post-Siwni, Tah. Marwahi, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
20. Kewal Goswami S/o Bishnu Bharti Aged About 44 Years R/o Kurma, Post-Dogri, Tah. Balauda, Distt. Janjgir-Champa, Chhattisgarh.
21. Sheikh Fafoof S/o Sheikh Chand Aged About 46 Years R/o Ward No. 2, Haldibadi, Chirmiri, District : Koriya (Baikunthput), Chhattisgarh.

22. Rajesh Kumar Mahant S/o Daroga Das Mahant Aged about 37 Years R/o House No. 63, Belakachhar, Village-Panchayat Condro, Post Balco Nagar, Tah. & Distt. Korba, Chhattisgarh.
23. Kamaldev S/o Ram Pratap Bangali Aged About 35 Years Dafaee, Heeragir Dafaee, Haldibadi, Post-Haldibadi, P.S. Chirmiri, Tah. Khadgavan, Pin-497451, District: Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.

— Respondents

For the Petitioner : In person.
 For Respondent No. 1 : Mr. R. S. Marhas, Advocate.
 For Respondent No. 2 : Mr. V. C. Ottalwar, Advocate

Hon'ble Shri Justice Goutam Bhaduri

CAV Judgment/Order

**Reserved on 21.02.2018
 Pronounced on 20.04.2018**

1. The present election petition touches upon the Parliamentary election held in the year 2014 for Korba constituency No. 4 Korba wherein respondent No. 1 Banshilal Mahto was declared elected as returned candidate. In such election respondent No. 1 who contested on behalf of Bhartiya Janta Party had secured 439002 number of votes and the petitioner who contested as an independent candidate has secured 1808 number of votes and the other respondents secured different number of votes.
2. (i) The challenge to the election of respondent No. 1 is on the ground that respondent no. 1 the returned candidate has not followed the mandatory direction/instructions issued by the chief Election Commissioner, Chhattisgarh and the affidavit in the required format was not submitted in the office of returning officer by all the respondents including the returned candidate (R-1). It is further case of the petitioner that the information was required to be submitted u/s 8 of the Representation of the People Act 1951 (hereinafter referred to as the "Act of 1951") by all the candidates who participated in the election but the respondents failed to file such papers before the election commission and therefore, the nomination of the election itself was void ab-initio. It is further case of the petitioner that the contesting candidates of the parliamentary election had to file nomination forms by 05-04-2014, which was the date prescribed for filing nominations in the office of Election commissioner, korba along-with affidavit. It was stated that the scrutiny of nominations was fixed for 07-04-2014 and the election was held on 24-4-2014. The counting of ballot papers was done on 16-05-2014 and the result was also declared on the same date.
- (ii) It was pleaded that the petitioner filed nomination form along-with affidavit in prescribed proforma as per the direction of the Commission, but respondent no. 1 and other contesting respondents have not submitted the affidavits as required u/s 8 of the Representation of People's Act 1951. The further case of the petitioner is on the ground that the direction of the Commission was required to be followed as a statutory mandate, however, the petitioner noticed that none of the respondents have submitted the affidavit and the information as required u/s 8 of the Act of 1951. Therefore, when the petitioner after noticing the deficiency in nomination papers of the other contesting candidates filed his objection before the returning officer, Korba and filed his affidavit, the same was ignored and the returning officer dismissed the objection by holding that the affidavit so enclosed by the returned candidate was in proper format. It is the case of the petitioner that the returned candidate primarily respondent No. 1 had filed the wrong nomination paper which was accepted by the returning officer and the same ought to have been dismissed in the initial stage when the objection was raised. Therefore, the election of returned candidate on such ground may be declared void.

3. The pleading of the election petition would show that the averments are being made against other respondents also who contested the election. However, during the course of trial, the petitioner did not much press upon such averments except the averments made against respondent No. 1 who is returned candidate, therefore, primarily while adjudicating the election petition, the court is concerned only with the nature of pleading and proof which is brought on record by the petitioner against respondent No. 1 whose election is sought to be set aside, The further allegation of the petitioner is that in the earlier election of 2009 the petitioner secured 23136 votes, however, in subsequent election it was reduced to 1808 for the reason that he was not provided any security and the transparency in the election process was absent, therefore, the election is also liable to be cancelled.
4. In the return, respondent No. 1 denied all the allegations and nothing was admitted. It is contended in reply that as per sub-section (3) of section 81 of the Representation of People's Act 1951 since the election petition was not accompanied by as many copies thereof as per the number of respondents mentioned in the petition and copies are not attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition, therefore, the petition is defectively filed.
5. It was further pleaded that the objection filed by the petitioner before the returning officer was rightly rejected as Section 8 of the Representation of People Act, 1951 prescribed for disqualification of a candidate only on conviction of candidates for certain offences and the objection did not contain any allegation of election petitioner that the respondent was convicted. It was further stated that the affidavit along-with nomination papers was properly sworn by the respondent and the scrutiny of proposal was also not disputed as the oath and affirmation was taken by the respondent in accordance with law. All the adverse allegations made in the petition were also denied.
6. on the basis of pleadings and averments made in the petition, the court has framed the following issues;

S. No.	Issues	Findings
01.	Whether copy of the election petition served to respondent No. 1 is attested by the petitioner under his own signature and whether the petition has been signed and verified by the election petitioner ? if not, the effect ?	Not Proved
02.	Whether the respondents have not submitted the affidavit and information under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 before the Returning Officer ? If not, the effect ?	Not Proved
03.	Whether the order Annexure P-2 rejecting objection filed by the election petitioner is wrong, illegal and void ?”	No
04.	Whether the returning officer acted illegally in not rejecting the nomination papers of the respondents ?	No
05.	Whether the election is liable to be quashed and whether the election petitioner is entitled to be declared as returned candidate?”	No

7. The petitioner examined himself before the Court and except this examination, no other evidence was adduced. On behalf of the respondent, returned candidate Dr. Bansilal Mahto was examined and Lakhnallal Dewangan was also examined on his behalf as D.W. 2.
8. Issues 2, 3& 4 are interlinked with each other as they are arising out of common facts and evidence as such these issues are being decided together. On behalf of the petitioner written submission have been filed and he did not appear on different dates so fixed for arguments. The learned counsel appearing on behalf of the

respondents, submits that the petitioner has not adduced any evidence to prove his case as such no case in made out in the election petition so as to declare the election of respondent No. 1 as void and except this, no submission has been made.

9. In order to find out the fact whether the election petitioner was able to prove his case beyond the reasonable doubt, the pleadings and evidence were examined. In the statement of the petitioner Shambhu Prasad Sharma, he has stated that on 07-04-2014 when the scrutiny was fixed before the returning officer, Korba, he had filed an objection that except the petitioner, no other candidate has filed the nomination forms according to the proforma set out by the election commission. It is stated that since the nomination papers should be filed according to the direction of the Election Commission, the entire candidatures of the nomination papers of other candidates should have been rejected. There is no admission of any document by the respondent, The petitioner has not exhibited or proved any document except the oral evidence. The petitioner has not called for any witness to prove the fact which nomination papers were filed by the returned candidate. If the petitioner was serious about the same to prove such facts, he could have called for the evidence of the returning officer to prove the document. Along-with the petition, bunch of photocopies of the documents have been placed, but the documents have not been exhibited and proved in evidence by calling the originals. The returned candidate in his reply has not admitted those documents and instead he has stated that they have filed the affidavit as per the requirement of law. Therefore, if the petitioner was certain of the fact that the nomination papers were not supported by duly sworn affidavit then in order to prove the same, the documents should have been called and proved before the Court when the documentary evidence exists. Only on mere say of the petitioner that the affidavit was not executed as per the direction and legally acceptable procedure, it cannot be taken to be a gospel truth for want of any evidence to accept the averments of the petitioner. The petitioner himself has failed to prove the nature of the documents which were filed by respondent No. 1 along-with affidavit when the nomination papers were filed.
10. As against the statement of the petitioner, respondent No. 1 who has examined himself has deposed that when he wants to file the nomination paper before the returning officer, Korba, he filled it before him and at the same time all the requisite documents were filed, He has stated that along-with documents, he has also filed the property papers. He has further stated that he had filled all the necessary forms and fulfilled the formalities and thereafter, the returning officer scrutinized the nomination form wherein no defect was found and having found that no defect exists, allowed him to contest the election. The respondent has further stated that it is wrong to assert that he has not filled the document as per the proforma of 6-1-98. He has further stated that his proposer Lakhan Lal Dewangan has also signed the nomination papers and admitted the fact that instead of full signature of Lakhan Lal Dewangan, he has signed as Lakhan Lal. It is further stated that the said proposer Lakhan Lal Dewangan is M.L.A., of Katghora constituency and he was elected prior to the election of the witness i.e., respondent No. 1.
11. In the cross examination of the petitioner, when he was subsequently asked as to why the copy of document i.e., format of 6.1.1998 has not been attached to the petition, it was replied by him that he had filed his objection before the returning officer and has stated about the objection in it. further when it was confronted that the returning officer has dismissed his plea holding that all the documents were in proper format, no reply was given instead it was stated that the returning officer was shown the format. Therefore, what is the format, where it exists was upon the petitioner to prove. Neither any such documents were summoned through proper authority nor any iota of evidence is on record to hold the form of affidavit sworn by the respondent was bad.
12. In the evidence of returned candidate, respondent No. 1, he stated that in his nomination form of election, the proposer Lakhan Lal Dewangan has signed the proposal form wherein he has made his signature as Lakhan Lal. The witness D.W. 2 Lakhan Lal Dewangan affirming the fact has stated that in the year 2014 he has signed as proposer of the nomination form of the returned candidate Bansilal Mahto and he has signed as Lakhan Lal in such paper.
13. The over all scrutiny of file would show that no documentary evidence is placed and exhibited by the petitioner in this case. The entire case is contested only on the presumption and oral evidence. The nature of pleadings and evidence would show that the petitioner has failed to appreciate that when he has come to the Court by filing election petition, it was his duty to satisfy the Court and discharge the burden of proof to substantiate the averments of the petition. Neither the copy of Annexure P-2 which was filed along-with the petition has been proved by the Original nor the Certified copy was called to prove the fact. Simply by placing a document, presumption cannot be drawn that it was the order dated 07-04-2014 passed by the returning officer whereby the objection of the petitioner was dismissed. What is the authority of the order and evidentiary value of it still remains mystery. To conclude, it is held that the petitioner was under duty to prove

- the fact that Annexure P-2 is result of objection made by the petitioner. The pleadings and the evidence are as vague as it could be and the petitioner has completely failed to discharge his burden of pleading and proof in the instant election petition.
14. In a case law reported in (1999) 1 SCC 666 - L. R. Shivarama Gowda vs. T. M. Chandrashekhar (para 10) Their Lordship of the Supreme Court have laid down the law that in order to declare an election to be void under Section 100 (1)(d)(iv), it is absolutely necessary for the election petitioner to plead that the result of the election so far as it relates to returned candidate has been materially affected by the alleged non-compliance with the provisions of the Act or of the rules. Now reverting the election petition, it would go to show that the specific pleading is absent about the fact that the election result has been materially affected for non-compliance of any rules or the provision. In the case in hand since the court is examining the allegation of election petition as against the will of the people, therefore, the necessary pleading to this effect has to be there in the election petition to hold that there is a violation of specific rules or direction issued by the Election Commission coupled with the fact that the result of the election of the returned candidate has been materially affected by the alleged non-compliance.
15. The Supreme court in case of **Jeet Mohinder Singh vs. Harminder Singh Jassi (1999) 9 SCC 386 in para 40** held that “the success of a candidate who has won at an election should not be lightly interfered with. Any petition seeking such interference must strictly conform to the requirements of the law. The Court further held that setting aside of an election involves serious consequences not only for the returned candidate and the constituency, but also for the public at large inasmuch as re-election involves an enormous load on the public funds and administration. Therefore, the inference is strict pleading of facts has to be followed by proof of facts.
16. In view of the pleadings and evidence, the court has no hesitation that the election petitioner has miserably failed to prove the pleadings and averments made by him. Neither any document has been exhibited which was attached with the petition by calling the original nor any officers were called to prove the same. Therefore, the photocopies of the documents attached with the petition remain as not proved. Consequently, no cognizance can be taken in this election petition about the existence of such document.
17. In the result, it is held that the petitioner has not been able to prove that the returning candidate has failed to give information as per section 8 of the R.P. Act 1951 nor is able to prove that the rejection of the objection raised by the returning officer was illegal and void. Further, the petitioner has been failed to prove that the returning officer acted illegally in not rejecting the nomination papers of the respondent thereby the petitioner has failed to prove issue nos. 2, 3 & 4.
18. With respect to issue no. 1 the said issue was primarily made on the pleading of the returned candidate that the petitioner had not served the petition under his signature and was not properly verified by him. In this respect, if the evidence of respondent No. 1 is seen it appears that the respondent was not serious to prove such fact and only superfluous statement has been made, therefore, only on the basis of averment in absence of any direct proof thereof the returned candidate has failed to discharge his burden as was raised by him which was framed under issue No. 1.
19. Therefore, on over all scrutiny of the entire pleadings and evidence, this court is of the opinion that the election petitioner has failed to prove the case beyond reasonable doubt. Consequently, the petition cannot be allowed or entertained only on presumption of facts and oral evidence in the result, the petition has no merit and is dismissed. No order as to costs.

Sd/-
GOUTAM BHADURI
JUDGE

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 12th June, 2018—22 Jyaistha, 1940 (Saka)

No. 82/CG-HP/(15/2014)/2018.—In pursuance of Section 106 (a) of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes Order dated the 20th April, 2018 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, in Election Petition No. 15 of 2014.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

EP. No. 15 of 2014

PETITIONER : Shambhu Prasad Sharma S/o Late Bansh Gopal Sharma Aged About 70 Years R/o Village And Post-Seoni, Tah. Marwahi, Civil & Revenue Distt. Bilaspur C.G. Chhattisgarh.

VERSUS

RESPONDENTS :

1. Dr. Banshilal Mahto S/o Late Dhaniram Mahto Aged about 73 Years R/o House No. 31, Ward No. 7, Champa Road, Main Road, Korba, Civil & Revenue Distt. Korba Chhattisgarh.
2. Charan Das Mahant S/o Bisahu Das Mahant Aged About 59 Years R/o House No. 623, Mahant Para, Post-Saragaon, Tah. Champa, Distt. Janjgir-Champa Chhattisgarh.
3. Heera Singh Markam S/o Late Dev Sai Markam Aged about 79 Years R/o Village & Post-Tiwrata, Tah. Pali, Civil & Revenue Distt. Korba Chhattisgarh.
4. Jeevan lal Rautel S/o Bisauha Ram Rautel Aged about 48 Years R/o House No. 224, Kolanpara, Village-Danauli, Post-Korja, Tah. Pendra Road, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
5. Amar Nath Pandey S/o Late Brajraj Pandey Aged About 48 Years R/o H.I.G. 128, M.P. Nagar, Korba Distt. Korba Chhattisgarh.
6. Dhan Singh Dhurve S/o Sri Rangae Dhurve Aged About 43 Years R/o Navgae, Post-Raghunath Nagar, Tah. Wadrafnagar, Surguja Division, Distt. Balrampur C.G., Pin-497225, Chhattisgarh.
7. Pratap Bhanu S/o Gulab Singh Aged About 45 Years R/o Village & Post-Semardarri, Tah. & Post-Marwahi, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
8. Charan Bhaiyya S/o Ramcharan Aged about 45 Years R/o Girari, Post-Nawagaon, Tah. Pendra Road, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
9. Jata Shankar Pandey S/o Jagdamba Aged About 38 Years R/o Salwa, Post-Ghuttra, P.S. Manendragarh, Distt. Korba C.G., District : Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.
10. S. R. Anchal S/o Late Mungeliha Das Aged about 44 Years R/o Dr. Ambedkar Chowk, House No. 632, Ward No. 39, Ayodhyapuri, Post-Ntpc Jamnipali, P.S. Darri, Distt.-Korba Chhattisgarh.
11. Chandra Bhuwan Pratap Singh Kanwar S/o Mool Chand Kanwar Aged about 36 Years R/o Jambahar, Post. Balco Nagar, Civil & Revenue Distt. Korba, Chhattisgarh.

12. Laxman Lal Kaiwarty S/o Birbal Aged About 44 Years R/o Purani Basti, Darri Post.-Jamnipali, Tah. Katghora, Distt. Korba, Chhattisgarh.
13. Phuleshwar Prasad Surjaeeha S/o Shambhunath Surjaeeha Aged about 71 Years R/o Dhinouchi, Post-Siwani, Tah. Marwahi, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
14. Rajesh Kumar Pandey S/o Bharat Kumar Pandey Aged About 42 Years R/o Old Kashinagar Khapra Bhattha, Budhwari Bazar, Korba, House No. 1106, Ward No. 16, Korba, Distt. Korba, Chhattisgarh.
15. Dr. Urmila Singh Marko D/o Rai Singh Marko Aged About 49 Years R/o Behind Secl Colony, Bandhwapara, Sarkanda, Bilaspur, Distt. Bilaspur Chhattisgarh.
16. Harbhajan Singh Shyam S/o Sumer Singh Aged About 33 Years R/o House No. L/101 Chief House Bartunga, Post.-Chirmiri, Tah. Khadgawan, Pin-497449, District : Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.
17. Rajendra Singh Kanwar S/o Late Jai Singh Kanwar Aged About 32 Years R/o House No. 563/1/3 Padhimar Balco Nagar, Distt. Korba Chhattisgarh.
18. Mohan Lal Bargahi S/o Ramadhin Bargahi Aged About 60 Years R/o Ward No. 09, South Jhagrakhand, Tah. Manendragarh, District : Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.
19. Fatte Singh Shyam S/o Jarman Singh Aged About 55 Years R/o Dhinouchi, Post-Siwani, Tah. Marwahi, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.
20. Kewal Goswami S/o Bishnu Bharti Aged About 44 Years R/o Kurma, Post-Dogri, Tah. Balauda, Distt. Janjgir-Champa, Chhattisgarh.
21. Sheikh Faooof S/o Sheikh Chand Aged About 46 Years R/o Ward No. 2, Haldibadi, Chirmiri, District : Koriya (Baikunthput), Chhattisgarh.
22. Rajesh Kumar Mahant S/o Daroga Das Mahant Aged about 37 Years R/o House No. 63, Belakachhar, Village-Panchayat Condro, Post Balco Nagar, Tah. & Distt. Korba, Chhattisgarh.
23. Kamaldev S/o Ram Pratap Bangali Aged About 35 Years Dafaee, Heeragir Dafaee, Haldibadi, Post-Haldibadi, P.S. Chirmiri, Tah. Khadgawan, Pin-497451, District: Koriya (Baikunthpur), Chhattisgarh.

— Respondents

For the Petitioner : In person.
 For Respondent No. 1 : Mr. R. S. Marhas, Advocate.
 For Respondent No. 2 : Mr. V. C. Ottalwar, Advocate

Hon'ble Shri Justice Goutam Bhaduri

CAV Judgment/Order

Reserved on 21.02.2018

Pronounced on 20.04.2018

1. The present election petition touches upon the Parliamentary election held in the year 2014 for Korba constituency No. 4 Korba wherein respondent No. 1 Banshilal Mahto was declared elected as returned candidate. In such election respondent No. 1 who contested on behalf of Bhartiya Janta Party had secured

439002 number of votes and the petitioner who contested as an independent candidate has secured 1808 number of votes and the other respondents secured different number of votes.

2. (i) The challenge to the election of respondent No. 1 is on the ground that respondent no. 1 the returned candidate has not followed the mandatory direction/instructions issued by the chief Election Commissioner, Chhattisgarh and the affidavit in the required format was not submitted in the office of returning officer by all the respondents including the returned candidate (R-1). It is further case of the petitioner that the information was required to be submitted u/s 8 of the Representation of the People Act 1951 (hereinafter referred to as the "Act of 1951") by all the candidates who participated in the election but the respondents failed to file such papers before the election commission and therefore, the nomination of the election itself was void ab-initio. It is further case of the petitioner that the contesting candidates of the parliamentary election had to file nomination forms by 05-04-2014, which was the date prescribed for filing nominations in the office of Election commissioner, Korba along-with affidavit. It was stated that the scrutiny of nominations was fixed for 07-04-2014 and the election was held on 24-4-2014. The counting of ballot papers was done on 16-05-2014 and the result was also declared on the same date.
- (ii) It was pleaded that the petitioner filed nomination form along-with affidavit in prescribed pro-forma as per the direction of the Commission, but respondent no. 1 and other contesting respondents have not submitted the affidavits as required u/s 8 of the Representation of People's Act 1951. The further case of the petitioner is on the ground that the direction of the Commission was required to be followed as a statutory mandate, however, the petitioner noticed that none of the respondents have submitted the affidavit and the information as required u/s 8 of the Act of 1951. Therefore, when the petitioner after noticing the deficiency in nomination papers of the other contesting candidates filed his objection before the returning officer, Korba and filed his affidavit, the same was ignored and the returning officer dismissed the objection by holding that the affidavit so enclosed by the returned candidate was in proper format. It is the case of the petitioner that the returned candidate primarily respondent No. 1 had filed the wrong nomination paper which was accepted by the returning officer and the same ought to have been dismissed in the initial stage when the objection was raised. Therefore, the election of returned candidate on such ground may be declared void.
3. The pleading of the election petition would show that the averments are being made against other respondents also who contested the election. However, during the course of trial, the petitioner did not much press upon such averments except the averments made against respondent No. 1 who is returned candidate, therefore, primarily while adjudicating the election petition, the court is concerned only with the nature of pleading and proof which is brought on record by the petitioner against respondent No. 1 whose election is sought to be set aside. The further allegation of the petitioner is that in the earlier election of 2009 the petitioner secured 23136 votes, however, in subsequent election it was reduced to 1808 for the reason that he was not provided any security and the transparency in the election process was absent, therefore, the election is also liable to be cancelled.
4. In the return, respondent No. 1 denied all the allegations and nothing was admitted. It is contended in reply that as per sub-section (3) of section 81 of the Representation of People's Act 1951 since the election petition was not accompanied by as many copies thereof as per the number of respondents mentioned in the petition and copies are not attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition, therefore, the petition is defectively filed.
5. It was further pleaded that the objection filed by the petitioner before the returning officer was rightly rejected as Section 8 of the Representation of People Act, 1951 prescribed for disqualification of a candidate only on conviction of candidates for certain offences and the objection did not contain any allegation of election petitioner that the respondent was convicted. It was further stated that the affidavit along-with nomination papers was properly sworn by the respondent and the scrutiny of proposal was also not disputed as the oath and affirmation was taken by the respondent in accordance with law. All the adverse allegations made in the petition were also denied.

6. on the basis of pleadings and averments made in the petition, the court has framed the following issues;

S. No.	Issues	Findings
01.	Whether copy of the election petition served to respondent No. 1 is attested by the petitioner under his own signature and whether the petition has been signed and verified by the election petitioner ? if not, the effect ?	Not Proved
02.	Whether the respondents have not submitted the affidavit and information under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 before the Returning Officer ? If not, the effect ?	Not Proved
03.	Whether the order Annexure P-2 rejecting objection filed by the election petitioner is wrong, illegal and void ?”	No
04.	Whether the returning officer acted illegally in not rejecting the nomination papers of the respondents ?	No
05.	Whether the election is liable to be quashed and whether the election petitioner is entitled to be declared as returned candidate?”	No

7. The petitioner examined himself before the Court and except this examination, no other evidence was adduced. On behalf of the respondent, returned candidate Dr. Bansilal Mahto was examined and Lakhanlal Dewangan was also examined on his behalf as D.W. 2.
8. Issues 2, 3& 4 are interlinked with each other as they are arising out of common facts and evidence as such these issues are being decided together. On behalf of the petitioner written submission have been filed and he did not appear on different dates so fixed for arguments. The learned counsel appearing on behalf of the respondents, submits that the petitioner has not adduced any evidence to prove his case as such no case in made out in the election petition so as to declare the election of respondent No. 1 as void and except this, no submission has been made.
9. In order to find out the fact whether the election petitioner was able to prove his case beyond the reasonable doubt, the pleadings and evidence were examined. In the statement of the petitioner Shambhu Prasad Sharma, he has stated that on 07-04-2014 when the scrutiny was fixed before the returning officer, korba, he had filed an objection that except the petitioner, no other candidate has filed the nomination forms according to the proforma set out by the election commission. It is stated that since the nomination papers should be filed according to the direction of the Election Commission, the entire candidatures of the nomination papers of other candidates should have been rejected. There is no admission of any document by the respondent, The petitioner has not exhibited or proved any document except the oral evidence. The petitioner has not called for any witness to prove the fact which nomination papers were filed by the returned candidate. If the petitioner was serious about the same to prove such facts, he could have called for the evidence of the returning officer to prove the document. Along-with the petition, bunch of photocopies of the documents have been placed, but the documents have not been exhibited and proved in evidence by calling the originals. The returned candidate in his reply has not admitted those documents and instead he has stated that they have filed the affidavit as per the requirement of law. Therefore, if the petitioner was certain of the fact that the nomination papers were not supported by duly sworn affidavit then in order to prove the same, the documents should have been called and proved before the Court when the documentary evidence exists. Only on mere say of the petitioner that the affidavit was not executed as per the direction and legally acceptable procedure, it cannot be taken to be a gospel truth for want of any evidence to accept the averments of the petitioner. The petitioner himself has failed to prove the nature of the documents which were filed by respondent No. 1 along-with affidavit when the nomination papers were filed.

10. As against the statement of the petitioner, respondent No. 1 who has examined himself has deposed that when he wants to file the nomination paper before the returning officer, Korba, he filled it before him and at the same time all the requisite documents were filed, He has stated that along-with documents, he has also filed the property papers. He has further stated that he had filled all the necessary forms and fulfilled the formalities and thereafter, the returning officer scrutinized the nomination form wherein no defect was found and having found that no defect exists, allowed him to contest the election. The respondent has further stated that it is wrong to assert that he has not filled the document as per the proforma of 6-1-98. He has further stated that his proposer Lakhan Lal Dewangan has also signed the nomination papers and admitted the fact that instead of full signature of Lakhan Lal Dewangan, he has signed as Lakhan Lal. It is further stated that the said proposer Lakhan Lal Dewangan is M.L.A., of Katghora constituency and he was elected prior to the election of the witness i.e., respondent No. 1.
11. In the cross examination of the petitioner, when he was subsequently asked as to why the copy of document i.e., format of 6.1.1998 has not been attached to the petition, it was replied by him that he had filed his objection before the returning officer and has stated about the objection in it. further when it was confronted that the returning officer has dismissed his plea holding that all the documents were in proper format, no reply was given instead it was stated that the returning officer was shown the format. Therefore, what is the format, where it exists was upon the petitioner to prove. Neither any such documents were summoned through proper authority nor any iota of evidence is on record to hold the form of affidavit sworn by the respondent was bad.
12. In the evidence of returned candidate, respondent No. 1, he stated that in his nomination form of election, the proposer Lakhan Lal Dewangan has signed the proposal form wherein he has made his signature as Lakhan Lal. The witness D.W. 2 Lakhan Lal Dewangan affirming the fact has stated that in the year 2014 he has signed as proposer of the nomination form of the returned candidate Bansilal Mahto and he has signed as Lakhan Lal in such paper.
13. The over all scrutiny of file would show that no documentary evidence is placed and exhibited by the petitioner in this case. The entire case is contested only on the presumption and oral evidence. The nature of pleadings and evidence would show that the petitioner has failed to appreciate that when he has come to the Court by filing election petition, it was his duty to satisfy the Court and discharge the burden of proof to substantiate the averments of the petition. Neither the copy of Annexure P-2 which was filed along-with the petition has been proved by the Original nor the Certified copy was called to prove the fact. Simply by placing a document, presumption cannot be drawn that it was the order dated 07-04-2014 passed by the returning officer whereby the objection of the petitioner was dismissed. What is the authority of the order and evidentiary value of it still remains mystery. To conclude, it is held that the petitioner was under duty to prove the fact that Annexure P-2 is result of objection made by the petitioner. The pleadings and the evidence are as vague as it could be and the petitioner has completely failed to discharge his burden of pleading and proof in the instant election petition.
14. In a case law reported in (1999) 1 SCC 666 - L. R. Shivarama Gowda vs. T. M. Chandrashekhar (para 10) Their Lordship of the Supreme Court have laid down the law that in order to declare an election to be void under Section 100 (1)(d)(iv), it is absolutely necessary for the election petitioner to plead that the result of the election so far as it relates to returned candidate has been materially affected by the alleged non-compliance with the provisions of the Act or of the rules. Now reverting the election petition, it would go to show that the specific pleading is absent about the fact that the election result has been materially affected for non-compliance of any rules or the provision. In the case in hand since the court is examining the allegation of election petition as against the will of the people, therefore, the necessary pleading to this effect has to be there in the election petition to hold that there is a violation of specific rules or direction issued by the Election Commission coupled with the fact that the result of the election of the returned candidate has been materially affected by the alleged non-compliance.
15. The Supreme court in case of **Jeet Mohinder Singh vs. Harminder Singh Jassi (1999) 9 SCC 386 in para 40** held that “the success of a candidate who has won at an election should not be lightly interfered with. Any petition seeking such interference must strictly conform to the requirements of the law. The Court further held that setting aside of an election involves serious consequences not only for the returned candidate and the constituency, but also for the public at large inasmuch as re-election involves an enormous load on the public funds and administration. Therefore, the inference is strict pleading of facts has to be followed by proof of facts.

16. In view of the pleadings and evidence, the court has no hesitation that the election petitioner has miserably failed to prove the pleadings and averments made by him. Neither any document has been exhibited which was attached with the petition by calling the original nor any officers were called to prove the same. Therefore, the photocopies of the documents attached with the petition remain as not proved. Consequently, no cognizance can be taken in this election petition about the existence of such document.
17. In the result, it is held that the petitioner has not been able to prove that the returning candidate has failed to give information as per section 8 of the R.P. Act 1951 nor is able to prove that the rejection of the objection raised by the returning officer was illegal and void. Further, the petitioner has been failed to prove that the returning officer acted illegally in not rejecting the nomination papers of the respondent thereby the petitioner has failed to prove issue nos. 2, 3 & 4.
18. With respect to issue no. 1 the said issue was primarily made on the pleading of the returned candidate that the petitioner had not served the petition under his signature and was not properly verified by him. In this respect, if the evidence of respondent No. 1 is seen it appears that the respondent was not serious to prove such fact and only superfluous statement has been made, therefore, only on the basis of averment in absence of any direct proof thereof the returned candidate has failed to discharge his burden as was raised by him which was framed under issue No. 1.
19. Therefore, on over all scrutiny of the entire pleadings and evidence, this court is of the opinion that the election petitioner has failed to prove the case beyond reasonable doubt. Consequently, the petition cannot be allowed or entertained only on presumption of facts and oral evidence in the result, the petition has no merit and is dismissed. No order as to costs.

Sd/-
GOUTAM BHADURI
JUDGE

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.
